NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 12, Dec. -2021

कोविड–19 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी MSMEs आर्थिक राहत पैकेज का आलोचनात्मक विश्लेषण

[1]Naveen Ram, [2]Dr. Sarika Verma, [3]Prof. Rajnish Pande
[1]Research Scholar, Department of Economics
D.S.B. Campus Nainital
Kumaun University Nainital, Mob.No. – 7060674065
Email – naveenram@kunainital.ac.in
[2]Assistant Professor, Department of Economics
D.S.B. Campus Nainital
Email – sarikav794@gmail.com
[3]Professor, Department of Economics
D.S.B. Campus Nainital
Kumaun University Nainital, Mob.No. – 9412084716
Email - rajnishpande@gmail.com

शोध सारांश

शोधार्थीयों द्वारा इस शोधपत्र में एमएसएमई पर कोविड–19 के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है तथा कोविड–19 महामारी के दौरान एमएसएमई को मिले आर्थिक राहत पैकेज का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है जिसके लिए शोधार्थीयों द्वारा द्वितीयक आंकडों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के लिए एमएसएमई उद्योग मंत्रालय व आर्थिक सर्वे साथ ही एमएसएमई की वार्षिक रिर्पोट का प्रयोग किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में कोविड–19 महामारी के दौरान मुख्य प्रभाव, निवेश मात्रा में वृद्धि तथा एमएसएमई परिभाषा परिवर्तन से सम्बन्धित है। जिसके कारण भविष्य में सूक्ष्म उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि सरकार द्वारा एमएसएमई उद्योगों की निवेश क्षमता बढ़ा दी गयी है। एमएसएमई को मिले आर्थिक पैकेज विश्लेषण में हमने पाया कि केवल 45 लाख फर्में कोलैट्रल फ्री लोन का फायदा ले पाये जोकि कुल अनुमानित एमएसएमई के केवल 7 प्रतिशत हैं।

शब्द संकेत – कोविड–19, MSMEs, आर्थिक राहत पैकेज, जीडीपी, केन्द्र सरकार

प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जोकि अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का महत्व इसलिये भी अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 28 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं। सेवा तथा निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई 111 मिलीयन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। भारत में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों तरह के 50 मिलियन या इससे अधिक MSMEs है और वे विनिर्माण का 45 प्रतिशत

और सेवा क्षेत्र का लगभग 24.7 प्रतिशत भाग का उत्पादन करते है।[1] इसी के साथ निर्यात में अकेले 40 प्रतिशत की भूमिका एमएसएमई उद्योगों की है। भारत में आज MSMEs के 12 करोड़ कर्मचारी है जो की कृषि के बाद रोजगार में दूसरे स्थान पर है, इसमें पुरूष कार्यबल का सर्वाधिक भाग है।[2] सूक्ष्म और लघु स्तर की कई इकाईयां अपने आकार और कम पूंजी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में आती है। MSMEs शहरी कामगारों तथा प्रवासी श्रमिकों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार प्रदान करते है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विमुद्रीकरण के बाद ऋणात्मक विकास दर पर चल रहे थे। नवम्बर 2016 से MSME की विकास दर 2 प्रतिशत ऋणात्मक चली गयी जबकि 2015 तक यह 6.8 प्रतिशत धनात्मक थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अपना लेन–देन कैश में कर रहे हैं परन्तु कैश की कमी ने MSME की विकास दर को रोक दिया और जैसे ही MSME अपने विकास दर को पकड़ रही थी, कि कोविड–19 ने दस्तक दे दी। जिसके चलते देशव्यापी तालाबन्दी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अनिश्चित समय की विपत्ति में घसीट दिया, जिसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म व लघु उद्योगों के श्रमिकों को रोजमर्रा की अवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा तथा कई प्रवासी श्रमिकों को अपना रोजगार छोड़ घर वापस लौटना पड़ा। इतना ही नहीं इस विपदा के चलते कई प्रवासी मजदूरों को अपनी जान भी गवानी पड़ी। स्थिति केवल मजदूरों की ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं की भी खराब हो गयी थी जिस कारण वे श्रमिकों को तऩख्वाह देने में तथा उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। साथ ही निवेशकों को अपने उद्योगों को आंशिक समय के लिए बन्द करना पडा।[3] जिस कारण सम्पूर्ण एमएसएमई सेक्टर विपत्ति में चला गया जिसको उभारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा MSMEs आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गयी।

साहित्य समीक्षा –

A.Roy, & Santpathy (2019) ने अपने शोध पत्र में आर्थिक पैकेज कि व्याख्या कि और बताया कि देशव्यापी तालाबन्दी में दिये गये आर्थिक पैकेज वास्तविक जरूरत से कम था। आर्थिक पैकेज से एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से नहीं उभरा पाया क्योंकि उससे निवेशकों को मिले राहत राशी से केवल जीएसटी, लोन तथा मजदूरी ही दी गयी, वास्तविकता में यह राशी इस कार्य के लिए भी अपर्याप्त थी।[4] Shah. & D.Pushakar

---

[1] www.msme.gov.ac.in

[2] Annual report of RBI, June 2018 , Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=924 on 14 -10 – 2020 at 11:25

[3] T.Agyeya, covid-19 affect on Micro, Small and Medium Enterprises, Sep.2020 on timesofindia.indiatimes.com

[4] A.Roy, Santpathy I., Impact of covid-19 crisis on Indian msme sector : A study on remedial measure

(2020) इन्होंने अपने शोध पत्र में एमएसएमई को मिला आर्थिक पैकेज की आलोचनात्मक व्याख्या की है। एमएसएमई उद्योगों के विकास में आर्थिक पैकेज की भूमिका कैसी रही इसकी चर्चा की है और तालाबन्दी में एमएसएमई मालिकों व वर्करों की स्थिति तथा वर्तमान परिदृश्य में एमएसएमई की स्थिति बताई है।[5] Sahoo. Pravakar, & Ashwani (2020) इन्होंने बताया पहले से मांग की कमी से ग्रसित एमएसएमई सेक्टर तालाबन्दी से और भी आहत हुआ, एमएसएमई के विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों पर तालाबन्दी का ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है।[6] Roy A. & Patnalk (2020) इन्होंने अपने शोध पत्र में कोविड – 19 के दौरान सरकार द्वारा लिये गये अग्रिम कदमों की व्याख्या की है तथा एमएसएमई को मिले आर्थिक पैकेज का पूर्ण विश्लेषण किया है।[7]

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है। जिसमें द्वितीयक ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु मुख्य रूप से एमएसएमई उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग किया गया है। शोध कार्य भारत के परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई उद्यगों पर आधारित है, जिसमें एमएसएमई से सम्बन्धित विभिन्न आकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

उद्देश्य

1. कोविड–19 के दौरान एमएसएमई के ढांचे में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना
2. कोविड–19 के दौरान एमएसएमई को मिले अर्थिक राहत पेकैज का विश्लेषण करना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का ढ़ाँचा – शोध के प्रथम उद्देश्य के लिए शोधार्थी के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में आये ढ़ाँचागत परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की वह शाखा है जो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से सम्बन्धित नियमों, विनियमों और कानूनों का निर्णय और प्रशासन सम्बन्धि कार्य के लिए सर्वोच्च निकाय है। एमएसएमई में बदलाव का निर्णय भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

---

[5] Shah.k.k, D.pushakar, msme in covid -19 crisis and Indian economy relief package : A critical review, 16 aug2020, reseach get

[6] Sahoo. Pravakar, D. Ashwani, covid-19 and Economy: Impact on growth, Manufacturing, Trade and msme sector

[7] Roy A. & Patnalk B.C.M,2020, Impact of Covid- 19 crisis ofn Indian MSME sector: A study on remedial measures, Eurasian Chemical communications

अधिनियम 2006 के अनुसार, भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को दो श्रेणीयों में बाँटा गया था। परन्तु वर्तमान केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् द्वारा 25 जून 2019 को एमएसएमई की परिभाषा में हुए परिवर्तन की सार्वजनिक रूप से घोषणा की।

1. विनिर्माण क्षेत्र 2. सेवा क्षेत्र

विनिर्माण क्षेत्र की परिभाषा सयंत्र और मशीनरी में कम्पनी के पूंजी निवेश पर आधारित है।

1- सूक्ष्म उद्योग :– वे सारे उद्योग जिनकी निवेशित पूंजी की राशी 25 लाख तक हो वे विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग कहलायेंगे तथा सेवा क्षेत्र के लिये यह सीमा 10 लाख रखी गयी थी। इन उद्योगों में अधिकांश तौर पर मालिक व उसका परिवार ही उत्पदन का कार्य कर रहे होते है तथा उत्पादन कार्य का अधिकतर भाग हाथों से किया जाता है।

2- लघु उद्योग :– विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योग वे कहलायेंगे जिनमें समस्त मशीनरी, मजदूरी तथा निवेशित पूंजी 25 लाख से 5 करोड़ तक हो तथा सेवा क्षेत्र के लिये यह मात्रा 10 लाख से 2 कारोड़ रखी गयी थी और जिनमें उत्पादन का अधिकांश कार्य विद्युत से होता हो।

3- मध्यम उद्योग :– विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्योगों में मशीनरी, मजदूरी तथा निवेशित पूंजी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ रखी गयी थी। सेवा क्षेत्र में इसकी सीमा 2 करोड़ से 5 करोड़ रखी गयी थी।[8]

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा में निवेशकों की निवेश क्षमता में वृद्धि की है और निवेशकों को अधिक निवेश के लिए प्रेरित किया है। नई परिभाषा में सेवा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र के अन्तर को खत्म किया गया तथा दोनों में निवेश व कारेबार की बराबरी कर दी गयी। निवेश की सीमा में वृद्धि की गयी साथ ही फर्म का टर्नओवर की मात्रा बढ़ायी गयी है। नई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई का स्वरूप इस प्रकार किया गया है।

1- सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें मशीनरी और सेवा में 1 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होता हो तथा उसका कारोबार 5 करोड़ से अधिक का न हो।

2- लघु उद्योग जिसमें मशीनरी और सेवा में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश हो तथा उसका कारोबार 50 करोड़ से अधिक का न हो।

3- मध्यम उद्योग वे है जिसमें मशीनरी और सेवा में 50 करोड़ से अधिक का निवेश होता हो तथा उसका कारोबार 250 करोड़ से अधिक का नहीं हो।[9]

---

[8] Ministry of MSME, retrieved https://www.mygov.in/task/poster-making-contest-national-road-safety-2021/?target=inapp&type=task&nid=324551 on 21-10-2021

[9] Msm
e gazette of India, june2020 retrieved https://msme.gov.in/ on 10-09-2021

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वितरण – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विश्वभर में लगभग 90 प्रतिशत व्यवसायों और 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार में योगदान देते हैं। एमएसएमई विकासशील देशों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 73वें चक्र के अनुसार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वितरण नीचे दी गयी सारणी 1.1 व आकृति 1.1 में दिया गया है।

सारणी 1.1 अनुमानित एमएसएमई उद्योगों की संख्या (लाख में)

मुख्य क्षेत्र	Estimated Number of Enterprises (in lakh)			**शेयर (%)**
	ग्रामीण	**शहरी**	**कुल**	
विनिर्माण	114.14	82.5	196.64	31
विद्युत	0.03	0.01	0.04	0
सेवा व अन्य	108.71	121.64	230.35	36
व्यापार	102	104.85	206.85	33
कुल	324.88	309	633.88	100

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 73वां चक्र

आकृति 1.1 अनुमानित एमएसएमई उद्योगों की संख्या (लाख में)

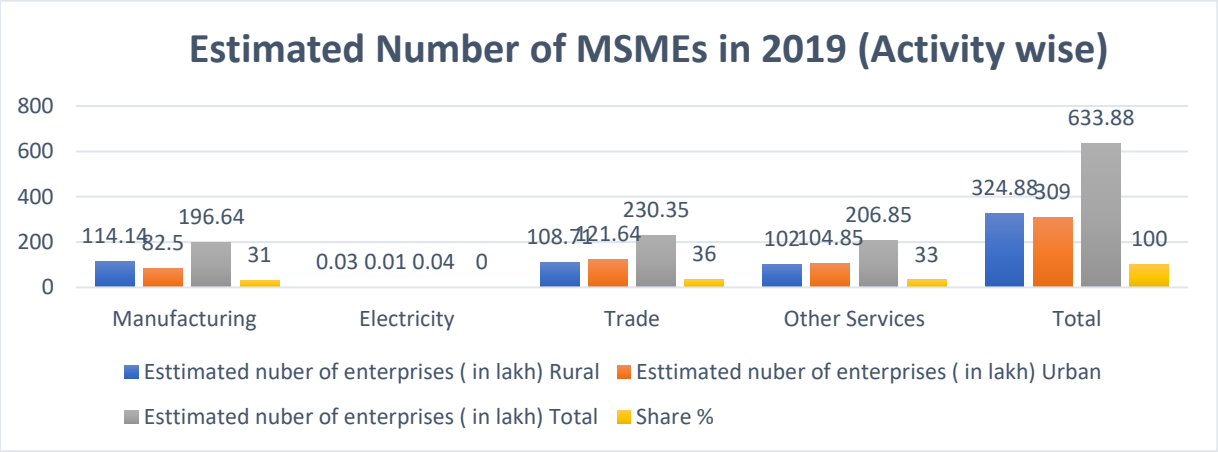

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 73वां चक्र

सारणी 1.1 तथा आकृति 1.1 में एमएसएमई उद्योगों की अनुमानित संख्या 633.88 लाख दी गयी है जिसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म व लघु उद्योगों की अधिकता है। जबकी शहरी क्षेत्रों में व्यापर और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई उद्योगों की अधिकता है। शहरी क्षेत्र में सेवा में 121.64

लाख एमएसएमई कार्यरत हैं तथा व्यापार क्षेत्र में 104.85 लाख़ एमएसएमई उद्योग कार्यरत हैं। जबकी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में एमएसएमई उद्योग व्यापार व सेवा दोनों में अधिक संलग्न हैं। वर्तमान में भारत में कुल 633.88 लाख एमएसएमई उद्योग हैं जिसमें से 324.88 लाख एमएसएमई उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 309 लाख एमएसएमई उद्योग शहरी क्षेत्रों में हैं।

MSMEs उद्योगों का रोजगार में योगदान :– राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 73वें चक्र के अनुसार, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में रोजगार का वितरण सारणी 1.2 में दिखाया गया है।

सारणी 1.2 MSMEs उद्योगों का रोजगार वितरण के आधार पर विवरण (डाटा लाख में)

मुख्य क्षेत्र	**MSMEs रोजगार का वितरण (लाख में)**			**शेयर (%)**
	ग्रामीण	**शहरी**	**कुल**	
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
विद्युत	0.06	0.02	0.07	0
सेवा व अन्य	160.64	226.54	387.18	38
व्यापार	150.53	211.69	362.22	33
कुल	497.78	612.10	1109.89	100

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 73वॉ चक्र

सारणी 1.2 में वास्तविक तौर पर एमएसएमई में 1109.89 लाख श्रमिक कार्यरत है। जिसमें से सेवा क्षेत्र में अत्यधिक श्रमिक कार्यरत हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में 226.54 लाख श्रमिक कार्यरत हैं तथा विद्युत क्षेत्र में सबसे कम 0.07 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। रोजगार की प्रकृति से शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में एमएसएमई की मुख्य भूमिका हैं क्योंकि यह शहरी क्षेत्र में 612.10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। सारणी 1.2 से यह भी स्पष्ट होता है, कि एमएसएमई द्वारा दिये गये कुल रोजगार में निर्माण क्षेत्र के द्वारा 38 प्रतिशत शेयर अकेले रोजगार प्रदान करने में है तथा व्यापार क्षेत्र के द्वारा 32 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है व 30 प्रतिशत रोजगार अन्य क्षेत्रों द्वारा दिया जा रहा है।

सारणी 1.3 ग्रामीण व शहारी क्षेत्र के आधार पर एमएसएमई उद्योगों का वितरण (डाटा लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	शेयर (%)
ग्रामीण	489.3	7.88	0.6	497.78	45
शहारी	586.88	24.06	1.16	612.1	55
All	1076.18	31.94	1.76	1109.88	100

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 73वॉ चक्र, (एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वार्ष 2021)

सारणी 1.3 में एमएसएमई उद्योगों का ग्रामीण व शहारी क्षेत्र के आधार पर रोजगार का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है। (NSSO) के 73वें चक्र के अनुसार एमएसएमई द्वारा 1109.88 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है, विनिर्माण क्षेत्र में 360.41 लाख तथा व्यापार क्षेत्र में 387.18 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। जिसमें विद्युत क्षेत्र का रोजगार प्रदान करने में सबसे कम योगदान है, जो कि 0.07 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराता है।

MSMEs के आर्थिक राहत पैकेज का विश्लेषण – भारत की केंद्र सरकार ने 13 मई 2020 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड–19 महामारी में एमएसएमई की मदद के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। यह पहल छोटे व्यवसायों के लिए कच्चे माल की खरीद, प्रारंभिक बिलों का भुक्तान और श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने और एमएसएमई को फिर से शुरू करने के लिए संसाधन लागत के रूप में कार्य करने में मदद करेगी। संक्षेप में, यह एमएसएमई व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में कार्य करेगा और इस आर्थिक राहत पैकेज के तहत कोलैट्रल फ्री लोन देने का वादा किया गया था। इस मद्द के कारण पहले जो बैंक, फर्मों को ऋण देने को तैयार नहीं थे वे तैयार हो गये, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये तक की पूरी गारंटी ली है और विशेष रूप से एमएसएमई उद्योगों के लिए इस सहायता की आवश्यकता थी क्योंकी एमएसएमई उद्योग ब्याज को चुकाने की स्थिति में नहीं थे। इनको कोलैट्रल फ्री लोन के द्वारा ही उभारा जा सकता था। (श्रीनिवासन, 2020)[10]

विस्तार से, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। यह 4 साल तक के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक–मुक्त स्वचालित ऋण (कोलैट्रल फ्री लोन) प्रदान करता है। यह योजना बैंकों को 100 प्रतिशत गारंटी के साथ मूलधन व ब्याज पर 45 लाख एमएसएमई को

[10] Srinivasan, R. (2020, May 17), "Coronavirus Package | How will the Covid-19 relief for MSMEs help?" Retrieved June 16, 2020, from https://www.thehindu.com/business/Economy/coronavirus-package-how-will-thecovid-19-relief-for-msmes-help/article31603575.ece

लाभान्वित करने के उद्देश्य से लागू की गयी जो 31 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध रही। सरकार एमएसएमई को फंड ऑफ फंड के रूप में व इक्विटी के रूप में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रही है। जिसको एमएसएमई की क्षमता और आकार को बढ़ाने के लिए मदर फंड और कुछ बेटी फंड के रूप में माना गया है। (बोरपुजरी, 2020)[11]

सरकार ने एमएसएमई को निवेश के साथ–साथ उनके टर्नओवर के आधार पर भी पुनः परिभाषित किया है। नई परिभाषा ने उत्पादन और सेवा इकाइयों के बीच पहले के अंतर को खत्म कर दिया है। नई परिभाषा में 1 करोड़ रुपये तक का निवेश व 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म इकाई कहा जाएगा, 10 करोड़ रुपये तक का निवेश व 50 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले उद्योगों को छोटी इकाइयों के रूप में जाना जाएगा, और 20 करोड़ रुपये तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर को मध्यम व्यावसायिक इकाई कहा जाएगा। (एमएसएमई उद्योग मंत्रालय जून 2019)[12]

निष्कर्ष

हमने एमएसएमई के आर्थिक पैकेज से सम्बन्धित साहित्य का विश्लेषण किया और पाया कि एमएसएमई को दिया गया आर्थिक पैकेज उद्यमियों के लिये प्रयाप्त नहीं था साथ ही अध्ययन में यह भी पाया कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में एमएसएमई उद्योगों को मिला आर्थिक पैकेज काफी कम था। कोलैट्रल फ्री लोन एमएसएमई के लिए एक वादा है जो सीधे समस्या को नहीं सुलझाता है क्योंकी बाद में लोन की राशि फर्मों को ही चुकानी पड़ेगी। सरकार द्वारा एमएसएमई को दिया गया आर्थिक राहत पैकेज मात्र मुद्रा की तत्कालीन तरलता की समस्या को ही सुलझाता है। जबकी भारतीय एमएसएमई को पूर्ण सहायता की आवश्यकता है।

वास्तव में बहुत ही कम एमएसएमई इस योजना से लाभ उठा पाये हैं। रियायती दरों पर कोलैट्रल फ्री लोन के लिए केवल वे ही फर्म योग्य हैं जिनके पास पहले से ही बकाया ऋण है। ये 45 लाख फर्में हैं जो कुल अनुमानित एमएसएमई का केवल 7 प्रतिशत हैं। अधिकांश सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिला।

---

[11] Borpuzari, P. (2020, May 25), "COVID-19 Relief: Government announces Rs. 3-lakh crore collateral-free automatic loans for MSMEs," Retrieved June 12, 2020, from https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/covid-19-reliefgovernment-announces-rs-3-lakh-crore-collateral-free-automatic-loans-formsmes/articleshow/75710137.cms?from=mdr

[12] https://msme.gov.in/know-about-msme

संदर्भ

1. www.msme.gov.ac.in
2. Annual report of RBI, June 2018, Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=924 on 14 - 10 – 2020 at 11:25
3. T. Agyeya, covid-19 effect on Micro, Small and Medium Enterprises, Sep.2020 on timesofindia.indiatimes.com
4. Shah.k.k, D.pushakar, msme in covid -19 crisis and Indian economy relief package : A critical review, 16 aug2020, reseach get
5. A.Roy, Santpathy I., Impact of covid-19 crisis on Indian msme sector : A study on remedial measure
6. Sahoo. Pravakar, D. Ashwani, covid-19 and Economy: Impact on growth, Manufacturing, Trade and msme sector
7. Roy A. & Patnalk B.C.M,2020, Impact of Covid- 19 crisis ofn Indian MSME sector: A study on remedial measures, Eurasian Chemical communications
8. Ministry of MSME, retrieved https://www.mygov.in/task/poster-making-contest-national-road-safety-2021/?target=inapp&type=task&nid=324551 on 21-10-2021
9. Msme gazette of India, june2020 retrieved https://msme.gov.in/ on 10-09-2021
10. Srinivasan, R. (2020, May 17), "Coronavirus Package | How will the Covid-19 relief for MSMEs help?" Retrieved June 16, 2020, from https://www.thehindu.com/business/Economy/coronavirus-package-how-will-thecovid-19-relief-for-msmes-help/article31603575.ece
11. Borpuzari, P. (2020, May 25), "COVID-19 Relief: Government announces Rs. 3-lakh crore collateral-free automatic loans for MSMEs," Retrieved June 12, 2020, from https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/covid-19-reliefgovernment-announces-rs-3-lakh-crore-collateral-free-automatic-loans-formsmes/articleshow/75710137.cms?from=mdr
12. https://msme.gov.in/know-about-msme